

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0'
2.	बिचून (जयपुर) में बनेगा माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
3.	वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान राशि में वृद्धि
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. पद्मश्री डॉ. एस. आर. मेहता का निधन 2. नया तंत्री वाद्ययंत्र 'कौडिन्य वीणा' 3. पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी 4. प्रेनेसी एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (PTCS) - 2.0 5. एशिया की सबसे बड़ी पानी की डिग्गी (आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर) 6. जय भगवान : एशियन बीच गेम्स कबड्डी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व 7. सहकारिता क्षेत्र (Cooperative Sector) में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में 8. 'बिल्ड विद एआई' वर्कशॉप
5.	एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, 2026
6.	अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, 2026
7.	डॉलर-रुपये का आदान-प्रदान
8.	एक राष्ट्र एक चुनाव
9.	शतायु डैशबोर्ड
10.	अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
11.	राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 2026
12.	युद्धपोत 'संघमित्रा'
13.	क्वांटम भौतिकी: क्वांटम मापन का नया तरीका
14.	स्काईरूट एयरोस्पेस
15.	नया AI मॉडल: क्लाउड मिथोस
16.	वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, 2026
17.	भारत में अनुसंधान एवं विकास सुगमता रिपोर्ट

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0'

चर्चा में क्यों?

- 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0' के अंतर्गत राजस्थान के 5 सीमांत जिलों; यथा - जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं फलौदी के 184 रणनीतिक महत्त्व के गाँवों में 10 विषयगत क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा।

मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0' सीमान्त क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पश्चात अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों का समग्र विकास करने संबंधी केन्द्र सरकार की दूसरी बड़ी योजना है।
- इस परियोजना के तहत इन गाँवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, ऑन ग्रिड विद्युतीकरण के क्षेत्र में शत-प्रतिशत संतृप्त किया जाएगा।
- साथ ही, इन गाँवों को आजीविका सृजन, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यटन एवं संस्कृति का विकास, आजीविका एवं कौशल विकास, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठनों का विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा।



वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0

- 4 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) - 2.0' को स्वीकृति प्रदान की।
- अवधि : वर्ष 2024-2029

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



प्रोग्राम का नाम	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम - 2.0
लॉन्च	2023	2025
राज्य	अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (UT), लद्दाख (UT), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा गाँवों में।
वित्त पोषण	शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा।	शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा।
उद्देश्य	सीमावर्ती गाँवों में जीवन स्तर में सुधार और आजीविका के अवसर सृजित करना। स्थानीय आबादी को सीमा बलों के समर्थन के रूप में शामिल करके सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना। सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना और सीमावर्ती समुदायों को देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत करना।	सीमावर्ती गाँवों में जीवन स्तर में सुधार और आजीविका के अवसर सृजित करना। स्थानीय आबादी को सीमा बलों के समर्थन के रूप में शामिल करके सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना। सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना और सीमावर्ती समुदायों को देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत करना।
संबंध मंत्रालय	गृह मंत्रालय।	गृह मंत्रालय।

--3--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** : राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषित की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने ₹150 करोड़ का प्रारंभिक बजट स्वीकृत किया है। कार्यक्रम के तहत राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गाँवों का समग्र विकास किया जाना प्रस्तावित है।

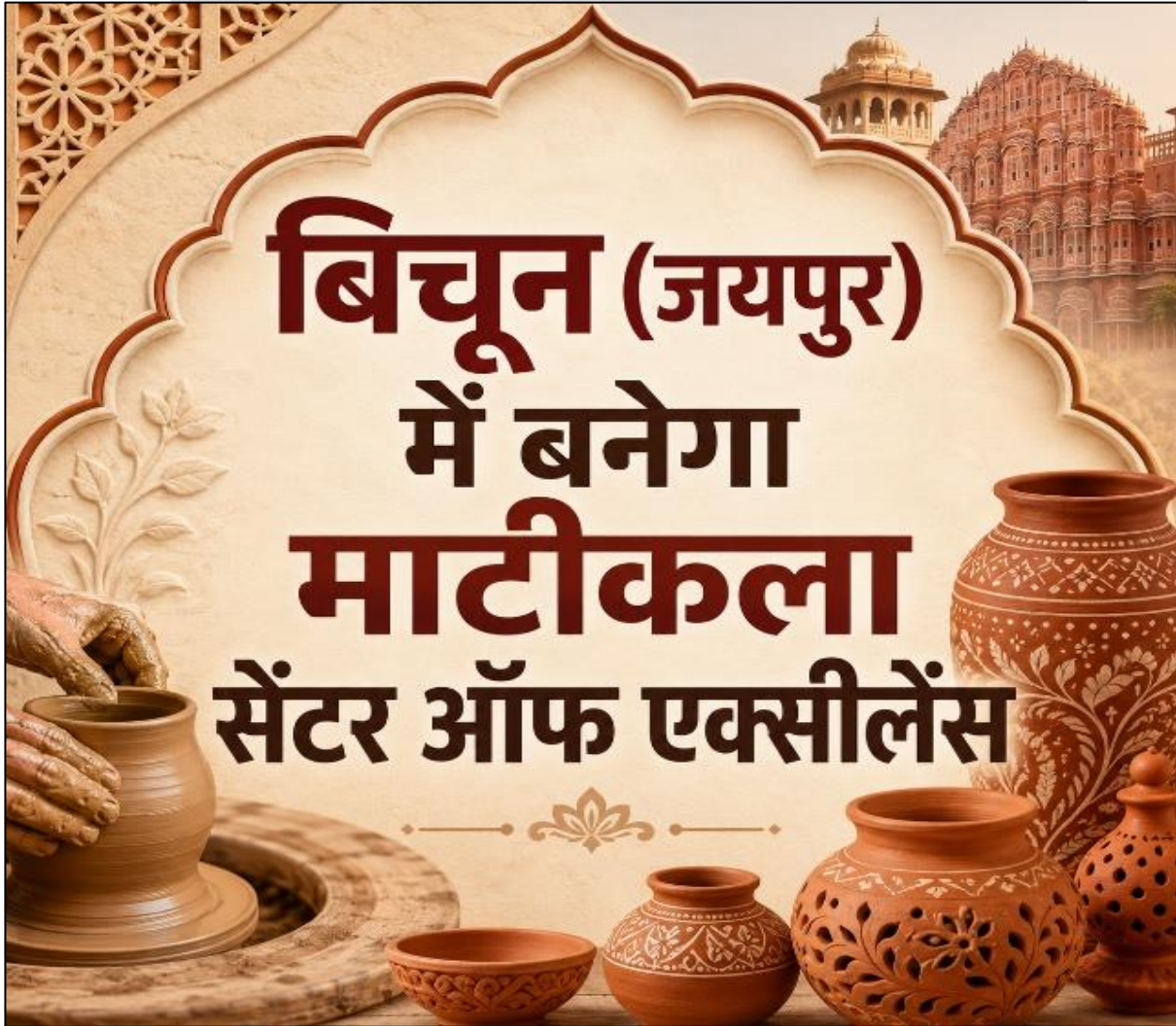


--:4:--

बिचून (जयपुर) में बनेगा माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, श्रीयादे माटी कला बोर्ड द्वारा बिचून (जयपुर) में 'माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाए जाने की घोषणा की गई।



मुख्य बिन्दु:

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मुख्य उद्देश्य:

- तकनीकी अपग्रेडेशन : कलाकारों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चाक और उन्नत भट्टियां प्रदान करना।

--:5:--

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- **उत्पाद विकास :** मिट्टी के बर्तनों के साथ-साथ डिजाइनर कलाकृतियाँ और टेराकोटा उत्पाद तैयार करना।
- **बाजार से जुड़ाव :** ग्रामीण कलाकारों को सीधे बड़े शहरों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
- **कौशल विकास :** युवाओं को माटी कला के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:**
- श्रीयादे माटी कला बोर्ड राज्य के माटी शिल्पियों और कुंभकारों (मिट्टी के कलाकार) के आर्थिक व तकनीकी विकास के लिए गठित एक प्रमुख बोर्ड है।
- **बोर्ड के अध्यक्ष :** प्रहलाद राय टाक।
- श्रीयादे माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदेश की विभिन्न माटी कला विधाओं में उत्कृष्ट 45 कलाकारों को 'माटी के लाल' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- **नोट :** राज्य बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के तहत 5,000 विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूँथने की मशीनों का वितरण किया जाएगा।
- **आवा-कजावा पद्धति :** राजस्थान में कुम्हार (प्रजापति) समाज द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली एक प्राचीन पद्धति है। इसका मुख्य उपयोग मिट्टी के बर्तन, खिलौने, कवेलू (छत की टाइलें) और ईंटें पकाने के लिए भट्टी तैयार करने में किया जाता है।
- राजस्थान सरकार द्वारा आवा-कजावा पद्धति से काम करने वाले माटीकला कामगारों के लिए वर्ष 2016 में गाइडलाइन बनाई गई।
- **श्रीयादे माता का पैनोरमा :** जोधपुर के झालामंड स्थित 'श्रीयादे माता पावन धाम'।

--:6::--

वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान राशि में वृद्धि



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए सम्मान राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

पत्रकार कल्याण और सम्मान के लिए, सरकार का अहम निर्णय

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने, वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान राशि में वृद्धि को दी मंजूरी

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की अधिसूचना

बजट घोषणा के अनुरूप, मिलेगी 18 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि

RajGovOfficial



मुख्य बिन्दु:

- **संबंधित विभाग :** सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR), राजस्थान।

प्रावधान :

- ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार, जिन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी में कम से कम 20 वर्षों तक सेवायोजन कार्य किया हो और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे प्रतिमाह ₹18,000 की सम्मान राशि के पात्र होंगे।
- साथ ही, वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत लाभार्थी दिवंगत पत्रकार की पत्नी को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि ₹7,500 से बढ़कर ₹9,000 हो गई है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (RJHS):

- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा 04 अप्रैल, 2025 को 'राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (RJHS)' की अधिसूचना जारी की गई।
- **योजना का शुभारंभ :** मुख्यमंत्री द्वारा भीलवाड़ा में 28 मार्च, 2025 को राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान किया गया था।
- योजना के तहत, राज्य सरकार से अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार RJHS के लिए पात्र होंगे। इस योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद अधिस्वीकृत पत्रकारों को RGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

पत्रकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना :

- 18 अप्रैल, 2025 को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा 'अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना' की अधिसूचना जारी की गई।
- यह योजना राज्य बजट 2024-25 की घोषणा के अनुरूप है, जो राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>पद्मश्री डॉ. एस. आर. मेहता का निधन</p> <ul style="list-style-type: none">जयपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक और सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पद्मश्री डॉ. एस. आर. मेहता का हाल ही में निधन हो गया।डॉ. एस. आर. मेहता को 16 मार्च, 1985 को तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने पद्मश्री से अलंकृत किया था।
2.	<p>नया तंत्री वाद्ययंत्र 'कौडिन्य वीणा'</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर के निदेशक और शास्त्रीय संगीत वादक डॉ. अश्विन एम. दलवी ने नया तंत्री वाद्ययंत्र 'कौडिन्य वीणा' तैयार किया।'कौडिन्य वीणा' अफगानी रबाब की ध्वनि से प्रभावित है। इसे चार अलग-अलग तंत्री वाद्यों की विशेषताओं को मिलाकर विकसित किया गया है।इस वाद्ययंत्र को आधिकारिक पेटेंट प्रदान किया गया है।
3.	<p>पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी</p> <ul style="list-style-type: none">बीकानेर निवासी पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी का जापान के आइची और नागोया में आयोजित होने वाले 'पैरा एशियन गेम्स' के लिए चयन हुआ।हरियाणा के सोनीपत में आयोजित चयन ट्रायल में श्याम सुंदर स्वामी ने दूसरा स्थान हासिल किया।
4.	<p>प्रेग्नेंसी एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (PTCS) - 2.0</p> <ul style="list-style-type: none">राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की ट्रेकिंग की मॉनिटरिंग के लिए संचालित प्रेग्नेंसी एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (PCTS) - 2.0 को अपग्रेड किया जा रहा है।संबंधित विभाग : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।राजस्थान में वर्ष 2008 से प्रेग्नेंसी एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (PTCS) लागू है।

5.	<p>एशिया की सबसे बड़ी पानी की डिग्गी (आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर)</p> <ul style="list-style-type: none">■ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा ₹242 करोड़ की लागत से जैसलमेर में एशिया की सबसे बड़ी पानी की डिग्गी (आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर) का निर्माण पूरा किया गया।■ यह महत्वाकांक्षी वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट रेगिस्तान में भीषण गर्मी और नहरबंदी के समय पानी के एक विशाल बैकअप सिस्टम के रूप में काम करेगा।■ इस वाटर रिजर्वर को इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (IGNP) के सरप्लस पानी और बारिश के पानी से भरा जाएगा।
6.	<p>जय भगवान : एशियन बीच गेम्स कबड्डी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व</p> <ul style="list-style-type: none">■ अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जय भगवान ने चीन के सान्या में आयोजित 6वें एशियन बीच गेम्स - 2026 में भारतीय पुरुष बीच कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता।■ संबंधित जिला : खैरथल-तिजारा।■ इसी प्रतियोगिता में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता।■ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट समुद्र तट और तटीय खेलों पर केंद्रित एक मल्टी-स्पोर्ट इवेंट है। इसकी शुरुआत 2008 में इंडोनेशिया के बाली में हुई थी।
7.	<p>सहकारिता क्षेत्र (Cooperative Sector) में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में</p> <ul style="list-style-type: none">■ सदस्यता में प्रथम : भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSL) की सदस्यता सूची में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है।■ PACS डिजिटलीकरण : PACS कम्प्यूटराइजेशन के तहत PACS को 'गो-लाइव' करने में राज्य का देश में दूसरा स्थान है। PACS का कम्प्यूटरीकरण भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश की सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों को डिजिटल बनाकर नाबार्ड और सहकारी बैंकों से जोड़ना है।■ e-PACS संख्या : इलेक्ट्रॉनिक पैक्स (e-PACS) की संख्या के मामले में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है।

8.

'बिल्ड विद एआई' वर्कशॉप

- हाल ही में, जयपुर स्थित राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT) में गूगल इंडिया के सहयोग से 'बिल्ड विद एआई' वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
- गूगल इंडिया के साथ हमारा यह सहयोग युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी प्लेटफॉर्म से लैस करने की राजस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



राष्ट्रीय परिदृश्य

एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, 2026

(स्रोत: DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, 2026 में महिलाओं की टीम रैंकिंग में तीसरा और पुरुषों की टीम रैंकिंग में पाँचवाँ स्थान हासिल किया।



मुख्य बिन्दु:

- मेजबानी: भारत
- आयोजन: 11 से 17 मई, 2026 तक गुजरात के गाँधीनगर शहर में आयोजित की गई।
- आयोजक: भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन

-:12:-

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- **भागीदार:** इसमें 30 देशों के 172 एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिनमें 97 पुरुष और 75 महिलाएँ थीं। इस चैंपियनशिप में महिलाओं की 8 और पुरुषों की 7 बॉडीवेट कैटेगरी थीं।

- **टीम रैंकिंग:**

रैंकिंग	महिला	पुरुष
1 st	चीन	चीन
2 nd	चीनी ताइपे	डीपीआर कोरिया
3 rd	भारत	उज्बेकिस्तान
4 th	श्रीलंका	चीनी ताइपे
5 th	बांग्लादेश	भारत

- **ओवरऑल मेडल टैली:** ओवरऑल मेडल टैली में, चीन ने 21 गोल्ड, 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दबदबा बनाया, उसके बाद डीपीआर कोरिया 18 गोल्ड, 11 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चीनी ताइपे 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर रहा।
- **भारत का प्रदर्शन:** भारत ने कुल 10 मेडल जीते, जिसमें एक सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे।
- **रिकॉर्ड:** आधिकारिक नतीजों के मुताबिक, चैंपियनशिप में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन हुए, जिसमें 27 एशियन रिकॉर्ड और 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने।
- **बेस्ट लिफ्टर:** डीपीआर कोरिया की री सुक को महिलाओं की बेस्ट लिफ्टर चुना गया। वहीं, चीन के ही यूजी पुरुष के बेस्ट लिफ्टर चुने गए।

--:13:--

भूगोल एवं भू-विज्ञान

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, 2026

(स्रोत: AIR, DD-NEWS और FAO)

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा प्रतिवर्ष 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है।

मुख्य बिन्दु:

- इतिहास:** लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व चीन में चाय की खोज हुई। प्रारंभिक काल में इसे औषधीय पेय माना जाता था।

--:14:--

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- **दिवस की स्थापना:** वर्ष 2019 में चाय पर अंतरसरकारी समूह ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर, 2019 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, 2020 को मनाया गया।
- **वर्ष 2026 का विषय:** "चाय को संरक्षित रखना, समुदायों का समर्थन करना" ("Sustaining Tea, Supporting Communities")।
- **उद्देश्य:** चाय उत्पादकों और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा। टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना। वैश्विक व्यापारिक असमानताओं को कम करना। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास में चाय उद्योग की भूमिका को रेखांकित करना। उपभोक्ताओं में जिम्मेदार उपभोग के प्रति जागरूकता विकसित करना।
- **भारत का चाय बाज़ार:** भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। केन्या, शीर्ष निर्यातक, अपनी उत्पादन की लगभग पूरी चाय निर्यात करता है, जबकि चीन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- भारत का चाय निर्यात बीते 12 वर्षों में वित्त वर्ष 2025-26 तक 93 प्रतिशत बढ़कर 8,719 करोड़ रुपए रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 में 4,509 करोड़ रुपए था।
- **चाय उत्पादक भारतीय राज्य:** असम (असम घाटी और कछार), पश्चिम बंगाल (दुआर, तराई और दार्जिलिंग), तमिलनाडु और केरल हैं, जो कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन करते हैं।
- संगठित क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग लगभग 12 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से लगभग 58 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- **भारतीय चाय बोर्ड:** चाय अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में और विदेशों में लंदन, दुबई और मॉस्को में कार्यालय हैं।

--:15:--

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

चाय (कैमेलिया साइनेंसिस):

■ विकास की परिस्थितियाँ:

- **जलवायु:** चाय एक उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय फसल है, जो गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अच्छी तरह उगती है।
- **तापमान:** यह 20°-30°C के मध्य।
- **वर्षा:** प्रतिवर्ष 150-300 से.मी. समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है।
- **मृदा:** थोड़ी अम्लीय, कैल्शियम-मुक्त मृदा और जल की स्वतंत्र निकासी के लिये छिद्रपूर्ण उप-मृदा उपयुक्त है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:16:-

आर्थिक घटनाक्रम

डॉलर-रुपये का आदान-प्रदान

(Source: Indian express)

चर्चा में क्यों?

- RBI ने तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ाने के लिए तीन साल की अवधि के लिए 5 बिलियन डॉलर के डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की है।



मुख्य बिन्दु:

- यह स्वैप, RBI की ओर से एक साधारण खरीद/ बिक्री विदेशी मुद्रा स्वैप की प्रकृति का है।
- एक बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर बेचेगा और साथ ही स्वैप अवधि के अंत में समान मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए सहमत होगा।

डॉलर-रुपया स्वैप

- यह विदेशी मुद्रा तरलता प्रबंधन का एक साधन है, जिसमें RBI अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये का विनिमय करता है तथा भविष्य में इस लेनदेन को वापस करने का समझौता होता है।
- **उद्देश्य:** रुपये की तरलता का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा बाजारों को स्थिर करना और विनिमय दर की अस्थिरता को कम करना।

--:17:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

एक राष्ट्र एक चुनाव

(Source: News on air)

चर्चा में क्यों?

- एक राष्ट्र, एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा कि लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और GDP संवृद्धि में 1.6% तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है।



मुख्य बिन्दु:

- JPC 'एक साथ चुनाव' से संबंधित दो प्रस्तावित कानूनों की जाँच कर रही है: संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024।

एक राष्ट्र, एक चुनाव:

- **आशय:** एक राष्ट्र, एक चुनाव का अर्थ है; सरकार के तीनों स्तरों—लोकसभा, राज्य विधानसभाएँ और स्थानीय निकायों (पंचायतें और नगरपालिकाएँ) के चुनाव एक साथ कराना।

महत्त्व:

- **वित्तीय बचत और विकास:** एक साथ चुनाव कराने से चुनाव कराने की लागत कम होगी और समय लेने वाली प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **नीतिगत पंगुता को रोकना:** बार-बार होने वाले चुनावों से 'आदर्श आचार संहिता' बार-बार लागू होती है। इससे विकास कार्य बाधित होते हैं।
- एक साथ चुनाव कराने से दीर्घकालिक विकास और कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा मिलेगा।
- **संसाधनों का संरक्षण और सतत शासन:** शिक्षकों और सुरक्षा बलों जैसी प्रशासनिक मशीनरी के बार-बार चुनाव कार्यों में लगाए जाने की प्रवृत्ति कम होगी।

'एक साथ चुनाव' की सिफारिश करने वाली विशेषज्ञ संस्थाएँ:

- भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट्स (1999 की 170वीं रिपोर्ट, 2015 की 255वीं रिपोर्ट, 2018 की ड्राफ्ट रिपोर्ट),
- संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (2015),
- नीति आयोग का वर्किंग पेपर (2017)।
- **पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (2023):** इस समिति ने 'एक साथ चुनाव' के चरणबद्ध कार्यान्वयन की सिफारिश की है—लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ, तथा उसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव।

कार्यान्वयन में चुनौतियां:

- **संवैधानिक और विधिक बाधाएँ:** संवैधानिक प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 83, 172, 327) में संशोधन और 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' में परिवर्तन करने होंगे।

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- **कार्यकाल पूरा होने से पहले विघटन:** "त्रिशंकु विधानसभा" होने या कार्यकाल पूरा होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरने की स्थिति में इस व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है।
- **लॉजिस्टिक्स की कमी:** एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनावी अवसंरचनाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता होगी। नीति आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया में अतिरिक्त EVM और VVPAT मशीनों के लिए लगभग 9,300 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ सकती है।
- **स्थानीय मुद्दों का गौण होना:** यह व्यवस्था स्थानीय मुद्दों के "राष्ट्रीयकरण" का कारण बन सकती है, जिससे क्षेत्रीय दल और स्थानीय विकासात्मक मुद्दे हाशिए पर जा सकते हैं।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:20:--

समाजशास्त्र

शतायु डैशबोर्ड

(स्रोत: AIR)



मुख्य बिन्दु:

- 22 मई, 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुव्यवस्थित देखभाल अर्थव्यवस्था के निर्माण पर एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप और वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं की जानकारी के लिए शतायु डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया।
- **उद्देश्य:** भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाते हुए देखभाल सेवाओं के लिए एक व्यापक ढाँचा विकसित करना।



सत्यमेव जयते

Ministry of Social Justice
and Empowerment



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

(Source: the Hindu)



चर्चा में क्यों?

- ताइवानी लेखिका और 'ताइवान ट्रेवलॉग' की लेखिका यांग शुआंग-ज़ी तथा अनुवादक लिन किंग ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2026 जीता।



मुख्य बिन्दु:

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

- यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक को प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- इसे 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था।

--:22:--

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के भारतीय विजेता:

- **गीतांजलि श्री (2022):** रेत समाधि (टॉम्ब ऑफ सैंड) के लिए, डेज़ी रॉकवेल द्वारा अनुवादित। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति थी।
- **बानू मुश्ताक (2025):** हार्ट लैंप पुस्तक के लिए। दीपा भास्थी द्वारा अनुवादित। इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति थी।
- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार से अलग है, जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई कृति को दिया जाता है।



--:23:--

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 2026

(स्रोत: PIB और DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की पुण्यतिथि के रूप प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस

21 मई

भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है।

इतिहास

- 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी।
- इस घटना के बाद वर्ष 1992 में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया।

उद्देश्य

- आतंकवाद और हिंसा के प्रति समाज को जागरूक बनाना।
- युवाओं को कट्टरवाद और उग्रवादी विचारधाराओं से दूर रखना।
- राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना।
- लोकतांत्रिक मूल्यों तथा शांति के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
- आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना।

--:24:--

मुख्य बिन्दु:

- **इतिहास:** 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या श्रीलंका के अलगाववादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के एक आत्मघाती हमलावर ने की थी।
- **उद्देश्य:** इस घटना के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा समाज में शांति और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया।
- **प्रथम:** 21 मई, 1992 (वी.पी. सिंह सरकार)
- **पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी:** राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्होंने वर्ष 1984 से वर्ष 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
- **संयुक्त राष्ट्र; आतंकवाद-विरोधी सप्ताह (CT सप्ताह):** चौथा CT सप्ताह 26 जून से 2 जुलाई, 2026 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में "आतंकवाद मुक्त भविष्य: सदस्य देशों के नेतृत्व और कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना" विषय के तहत आयोजित किया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

आतंकवाद : अवधारणा, स्वरूप और बदलती प्रकृति

- **अवधारणा:** 'आतंकवाद' शब्द का मूल अर्थ भय या आतंक उत्पन्न करना है। सामान्यतः यह किसी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अथवा वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा और भय का योजनाबद्ध प्रयोग है। इसका लक्ष्य केवल जनहानि नहीं, बल्कि समाज की मानसिक संरचना और राष्ट्रीय स्थिरता को प्रभावित करना भी होता है।

प्रमुख स्वरूप:

- **पारंपरिक आतंकवाद:** बम विस्फोट, गोलीबारी, अपहरण, सामूहिक हिंसा और प्रत्यक्ष हमले इसके प्रमुख रूप हैं।
- **धार्मिक कट्टरता आधारित आतंकवाद:** धार्मिक विचारों की संकीर्ण एवं हिंसक व्याख्या के माध्यम से हिंसा को उचित ठहराने का प्रयास किया जाता है।
- **अलगाववादी आतंकवाद:** जब कोई समूह क्षेत्रीय अथवा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसक मार्ग अपनाता है।
- **साइबर आतंकवाद:** डिजिटल युग में कंप्यूटर नेटवर्क, बैंकिंग प्रणाली, ऊर्जा तंत्र तथा संचार व्यवस्था पर हमले इसका नया रूप बन चुके हैं।
- **जैविक और रासायनिक आतंकवाद:** रासायनिक अथवा जैविक एजेंटों के माध्यम से बड़े स्तर पर विनाश करने का प्रयास।
- **अकेले हमलावर (Lone Wolf) आतंकवाद:** इसमें कोई व्यक्ति किसी विचारधारा से प्रभावित होकर बिना किसी प्रत्यक्ष संगठनात्मक संबंध के हिंसक हमला कर सकता है।
- आधुनिक समय में आतंकवाद की प्रकृति तेजी से बदल रही है। अब यह केवल भौतिक हमलों तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी उपयोग कर रहा है।
- **आतंकवाद के प्रमुख कारण:** आतंकवाद किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक कारकों का संयुक्त प्रभाव है। इसके प्रमुख कारण हैं: राजनीतिक अस्थिरता और छद्म युद्ध, धार्मिक कट्टरता एवं वैचारिक उग्रवाद, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी, सामाजिक उपेक्षा और असंतोष, विदेशी हस्तक्षेप, तकनीक और सोशल मीडिया का दुरुपयोग और युवाओं का कट्टरपंथीकरण। इन परिस्थितियों में उत्पन्न असंतोष और भ्रमित विचारधाराएँ कई बार हिंसक गतिविधियों का आधार बन जाती हैं।

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- **भारत की प्रमुख आतंकवादी घटनाएँ:** वर्ष 1993 में बाम्बई में बम हमले, वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमला, वर्ष 2008 में मुम्बई पर हमला, वर्ष 2019 में पुलवामा हमला।

भारत के प्रयास:

- **नई नीति 'प्रहार' (2026):** गृह मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी, 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति 'प्रहार' (PRAHAAR) शुरू की गई है, जो खुफिया-आधारित और 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
- **जीरो टॉलरेंस नीति:** भारत वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance Policy) की नीति अपनाता है।
- **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008:** 26/11 के मुंबई हमलों के बाद इसका गठन किया गया, NIA विभिन्न राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करता है, जिससे एक केंद्रीकृत, विशिष्ट जाँच तंत्र सुनिश्चित होता है।
- **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967:** यह प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कानून सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्ति ज़ब्त करने और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।

-:27:-

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⌚

युद्धपोत 'संघमित्रा'

(स्रोत: PIB और DD-NEWS)

📢 चर्चा में क्यों?

- 20 मई, 2026 को कोलकाता गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहले नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (NGOPV) 'संघमित्रा' का जलावतरण किया।



📌 मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया पहला नेक्स्ट-जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (NGOPV - यार्ड 3039) है।

--:28:--

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- **'संघमित्रा' का अर्थ:** समाज की मित्र, इस पोत का नाम 'संघमित्रा' सम्राट अशोक की पुत्री के नाम पर रखा गया है। जहाज के प्रतीक चिह्न में सप्तऋषि तारामंडल और लाल-सफेद रंग के प्रकाश स्तंभ को दर्शाया गया है।
- **नाम:** यार्ड 3039
- **कार्य:** स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और निर्मित ये युद्धपोत समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान और समुद्री डकैती रोधी अभियानों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- **विशेषताएँ:** यह लगभग 113 मीटर लंबा और 14.6 मीटर चौड़ा होगा, जिसका विस्थापन 3,000 टन है। यह पोत 23 नॉट्स की गति प्राप्त कर सकता है और 14 नॉट्स की रफ्तार पर 8,500 नौटिकल मील तक की सहनशक्ति रखता है।
- भारतीय नौसेना के लिए कुल 11 नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण किया जा रहा है। इन जहाजों का निर्माण दो शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा और GRSE, कोलकाता में एक साथ किया जा रहा है।

--:29:--

क्वांटम भौतिकी: क्वांटम मापन का नया तरीका

(स्रोत: DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने क्वांटम भौतिकी में एक ऐसे व्यवहार का पता लगाया है, जो यह दर्शाता है कि कभी-कभी विपरीत अवस्थाओं में तैयार किए गए दो कण, समान अवस्थाओं वाले कणों की तुलना में अधिक जानकारी दे सकते हैं।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज भविष्य में क्वांटम उपकरणों के परीक्षण और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी तकनीकों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती है।



मुख्य बिन्दु:

- **शोध:** एस. एन. बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र, बालागढ़ विजॉय कृष्ण महाविद्यालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया।

--:30:--

क्वांटम भौतिकी की मूलभूत सीमा पर नया दृष्टिकोण:

- क्वांटम भौतिकी में किसी प्रणाली के सभी गुणों को एक साथ पूरी सटीकता से जान पाना संभव नहीं होता। इस सीमा को बोहर का पूरकता सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि कुछ क्वांटम गुणों को एक साथ पूरी परिशुद्धता के साथ मापा नहीं जा सकता।
- इसके प्रसिद्ध उदाहरणों में डबल-स्लिट प्रयोग में पथ सूचना और व्यतिकरण दृश्यता के बीच संतुलन, या स्थिति और संवेग जैसी गैर-परिवर्तनशील प्रेक्षणीयताओं का संयुक्त मापन शामिल है।
- **समानांतर और विपरीत समानांतर स्पिन पर अध्ययन:** इन युग्मों को दो अलग-अलग तरीकों से तैयार किया गया। पहले प्रकार में दोनों स्पिन एक ही दिशा में रखे गए, जिसे समानांतर अवस्था कहा गया, जबकि दूसरे प्रकार में दोनों स्पिन एक-दूसरे के विपरीत दिशा में थे, जिसे विपरीत समानांतर अवस्था कहा गया है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि विपरीत समानांतर स्पिन तीन परस्पर असंगत स्पिन घटकों की एक साथ अधिक सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं। वहीं समानांतर स्पिन के साथ ऐसा करना मूलभूत रूप से संभव नहीं है।
- **निष्कर्ष:** यह निष्कर्ष क्वांटम सिद्धांत की बुनियादी समझ को चुनौती देता है। शास्त्रीय भौतिकी में कई गुणों का मापन केवल तकनीकी सीमाओं तक सीमित माना जाता है, लेकिन क्वांटम प्रणालियाँ अपनी आंतरिक सीमाएँ तय करती हैं।
- **हाइजेनबर्ग और बोहर के सिद्धांतों से जुड़ा अध्ययन:** यह अध्ययन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और बोहर के पूरकता सिद्धांत जैसे मूलभूत सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। शोध के अनुसार, यदि क्वांटम अवस्थाओं को विशेष तरीके से तैयार किया जाए, तो कुछ सीमाओं को अप्रत्याशित ढंग से पार किया जा सकता है।

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- यह शोध याकिर अहारोनोव और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित प्रसिद्ध क्वांटम पहेली 'मीन किंग्स प्रॉब्लम' से भी संबंधित है।
- **उपयोग:** विपरीत समानांतर कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम उपकरणों के अधिक प्रभावी परीक्षण और विश्लेषण में उपयोगी हो सकता है। यह भविष्य में विश्वसनीय क्वांटम तकनीकों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- इसके अलावा, यह खोज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जहाँ सीमित क्वांटम संसाधनों से अधिकतम जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:32:--

स्काईरूट एयरोस्पेस

(स्रोत: DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- स्पेस-टेक स्काईरूट एयरोस्पेस ने 60 मिलियन डॉलर (भारतीय रुपए में करीब 570 करोड़ रुपए) जुटा कर देश की पहली स्पेस-टेक स्टार्टअप यूनिर्कॉर्न बन गई है।



मुख्य बिन्दु:

- **स्काईरूट की वैल्यूएशन:** मौजूदा फंडिंग राउंड में स्काईरूट की वैल्यूएशन 1.1 अरब डॉलर रही है, जो कि 2023 में कंपनी की वैल्यू से 519 मिलियन डॉलर से करीब चार गुना ज्यादा है।
- **यूनिर्कॉर्न:** जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन एक अरब डॉलर से अधिक हो जाता है तो उसे यूनिर्कॉर्न माना जाता है।
- नई पूँजी से स्काईरूट को विक्रम-1 के प्रक्षेपणों को तेज गति से स्थापित करने, उत्पादन बढ़ाने और विक्रम-2 (एक उन्नत क्रायोजेनिक चरण द्वारा संचालित 1 टन श्रेणी का प्रक्षेपण यान) विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **स्काईरूट एयरोस्पेस:** हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और CEO पवन कुमार चंदना हैं।

नया AI मॉडल: क्लाउड मिथोस

(स्रोत: DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- क्लाउड मिथोस (Claude Mythos) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) द्वारा विकसित एक नया, अत्याधुनिक और अत्यधिक शक्तिशाली AI मॉडल है।



मुख्य बिन्दु:

- परिचय:** क्लॉड मिथोस, एंथ्रोपिक का नवीनतम बड़ा भाषा मॉडल है। इसमें उन्नत कोडिंग, तर्क और स्वायत्त क्षमताएँ हैं, जो इसे एक "सामान्य-उद्देश्य" मॉडल बनाती हैं। मिथोस सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करने में उत्कृष्ट है।

--:34:--

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



विशेषताएँ:

1. एंथ्रोपिक के अनुसार , मिथोस ने सभी प्रमुख वेब ब्राउज़रों और ऑपरेटिंग सिस्टमों में हजारों बग का पता लगाया है, जिनमें ओपनबीएसडी (एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने सुरक्षा उपायों के लिए प्रसिद्ध है) में पाया गया एक बग भी शामिल है, जो 27 वर्षों तक अनदेखे रहा था।
2. सॉफ्टवेयर की कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम।
3. ज़ीरो-डे वलनरेबिलिटी खोज और उनका फायदा उठाने में दक्ष।

चिंताएं:

1. मॉडल बिना मानवीय सहायता के एक्सप्लॉइट विकसित कर सकता है।
2. कम तकनीकी ज्ञान वाले लोग भी साइबर हमले कर सकते हैं।
3. स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन और बैंकिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर खतरा बढ़ सकता है।

--:35:--

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, 2026

(Source: Hindustan times)

चर्चा में क्यों?

- यूएन-हैबिटेट की यह रिपोर्ट "द ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस: पाथवेज़ टू एक्शन" शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि आवास की वहनीयता से जुड़ी समस्याएँ, व्यापक अनौपचारिकता या गैर विनियमित आवासीय इकाइयाँ और बढ़ते जलवायु-संबंधी जोखिम आदि आपस में जुड़े हुए और एक-दूसरे को गंभीर करने वाली चुनौतियाँ हैं।

मुख्य बिन्दु:

- **आवास संकट का दायरा:** विश्व भर में लगभग 3.4 अरब लोगों के पास पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ नहीं हैं।
- **अनौपचारिक बस्तियाँ:** लगभग 1.1 अरब लोग झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रह रहे हैं, जहाँ मूलभूत शहरी सेवाओं और अवसंरचनाओं का अभाव है।
- **जलवायु संबंधी खतरे:** रिपोर्ट का अनुमान है कि 2040 तक जलवायु संबंधी खतरों के कारण 167 मिलियन घर नष्ट हो सकते हैं।
- आवासन क्षेत्रक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 17-21% के लिए जिम्मेदार है।
- **अप्रभावी राष्ट्रीय आवासन नीतियाँ:** विश्व भर में औसत आवास मूल्य-आय अनुपात 2010 के 9.5 से बढ़कर 2023 में 11.7 हो गया। इसका अर्थ है कि एक घर की कीमत, एक औसत परिवार की वार्षिक आय से 11.7 गुना तक हो सकती है।
- भारत के संदर्भ में, मुंबई और दिल्ली में यह अनुपात क्रमशः 14.3 और 10.1 दर्ज किया गया।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

- **समग्र किफायती रणनीतियाँ:** भूमि शासन को मजबूत करना, किराये और गैर-बाजार आधारित आवासीय विकल्पों का विस्तार करना, विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- **आवास खरीदने के लिए सुलभ वित्तपोषण:** अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों एवं महिला-प्रधान परिवारों सहित कमजोर और कम आय वाले समूहों को वित्तपोषण में प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **जलवायु-अनुकूल नीतियाँ:** आवासन नीतियों में 'ग्रीन जेंट्रीफिकेशन' (पर्यावरण में सुधार के नाम पर गरीबों का विस्थापन) जैसी बहिष्करण नीतियों और हरित भूमि हड़पने वाली प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

भारत में अनुसंधान एवं विकास सुगमता रिपोर्ट

(Source: नीति आयोग)

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने "भारत में अनुसंधान एवं विकास सुगमता रिपोर्ट" जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) जीडीपी का लगभग 0.65% है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका (लगभग 3.5%), चीन (लगभग 2.4%) और कोरिया गणराज्य (लगभग 4.5%) की तुलना में कम है।

मुख्य बिन्दु:

- इसके अतिरिक्त, वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष शोधकर्ताओं की संख्या 262 है, जबकि अमेरिका में यह 4,821 और चीन में 1,585 है।

भारत की अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रणाली की मुख्य चुनौतियाँ:

- R&D में अपर्याप्त वित्तपोषण:** भारत में न केवल सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय कम है, बल्कि यह सार्वजनिक यानी सरकारी वित्तपोषण (लगभग 64%) पर अत्यधिक निर्भर है। वहीं, अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में R&D बजट का 60% निजी क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है।
- गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन को आकर्षित करना:** शोधकर्ताओं को अपने पेटेंट को उत्पादों में बदलने के लिए प्रोत्साहन की कमी के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
- प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक उपयोग और व्यावसायीकरण:** बहुत कम अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, जैसे CSIR प्रयोगशालाओं, में तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग और व्यावसायीकरण से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग हैं।

Daily Current Affairs

Date : 22 May, 2026



- **राज्य संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (R&D):** R&D के लिए कम वित्तपोषण और कमजोर बुनियादी ढाँचे प्रमुख समस्याएँ हैं। साथ ही, संबद्धता से जुड़े नियमों के अनुपालन में शिक्षकों का अधिकतम समय और ऊर्जा बर्बाद होता है।

मुख्य सिफारिशें:

- सकल R&D व्यय को बढ़ाकर GDP का कम से कम 2% करना चाहिए।
- फेलोशिप के वित्तपोषण और वितरण में होने वाली देरी को दूर करने के लिए 'विज्ञान निधि' नामक एकीकृत फेलोशिप प्रणाली बनाई जाए।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों, R&D संस्थानों, MSMEs, PSUs और उद्योग जगत को एकीकृत करके राज्य-स्तरीय RDI क्लस्टर गठित किए जाएं।
- दक्षिण कोरिया की STEPI और जापान की NISTEP पहलों की तर्ज पर नीति, कार्यान्वयन और निगरानी से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान नीति एवं शासन संस्थान (NISPG) की स्थापना की जा सकती है।

-:39:-